(c) what are the details of the defence research programmes which have not been taken up or the progress in respect of which has been slow stating the reasons therefor; and

(d) what steps have been taken by Government to step up the defence research programmes?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR: (a) Salient features of major programmes undertaken during the eighties by the Defence R&D Organisation (DRDO) are: multi-disciplinary approach, specific orientation towards qualitative requirements given by the user Services, emphasis on state-of-the-art technology, shift towards *ab-initio* design & development of major defence systems and following up the programme upto successful user trials.

(b) Half of the major development projects taken up during the eighties have either been completed or are undergoing trails & evaluation; 20% are in advanced stage of system integration and 30% are in detailed design and engineering stage.

(c) Two programmes for setting up test/assembly facilities and two programmes for development of airborne vehicles have time over-runs compared to their original time frames. The reasons mainly have been inherent uncertainties/ risks due to high technologies involved, lack of adequate technological infrastructure in the country, labour problem in the public sector undertaking involved, fire in the public sector undertaking, setting up the fabrication and assembly facility and export restrictions by other countries.

(d) Steps taken to strengthen the defence research programmes include setting up/upgrading test facilities particularly in high-tech areas, increased thrust on indigenous development of critical materials / components, introduction of efficient project management techniques & procedures, interaction with user Services & production agencies and adopting philosophy of concurrent development & production to reduce development-production time cycle.

छावनी क्षेत्र में किराए के आवास

3039. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के पास छावनी क्षेत्रों में किराए के आवास हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा कुल कितने किराए का भुगतान किया गया; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय ने कुछ आवासों को खाली करने का निर्देश दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नई छावनियां स्थापित किया जाना

3040. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में नई छावनियां स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अवेरी नामक स्थान पर नई छावनी स्थापित किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभाव (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) और (ख): जी, नहीं। छावनी अधिनियम, 1924 के तहत मौजूदा नीति स्टेशन स्थापित करने की है न कि छावनियां।

(ग): सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित अवेरी गांव में सैन्य स्टेशन स्थापित करने के लिए 273.54 एकड़ गैर-सरकारी भूमि के अधिग्रहण तथा राज्य सरकार की 95.19 एकड़ भूमि के अन्तरण के वास्ते मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की भूमि के अधिग्रहण/अन्तरण के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।